



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

पत्रांक- 506/1सी0 (वन)

दिनांक 2/4 /2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय- प्रस्ताव सं० **FP/UK/ROAD/19786/2016** राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

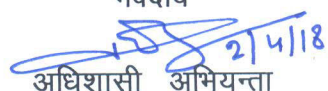
सन्दर्भ:- आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 14.2.2018 , 20.3.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक सं० 329/1सी0 वन दिनांक 14.2.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 20.3.2018 द्वारा लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर आपत्तियाँ लगाई गई हैं, जिसका बिन्दुवार निराकरण कर आख्या प्रेषित की जा रही है:-

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	FRA not complted . Please remove the objection	एफ0आर0ए0 पूर्ण कर निर्धारित कॉलम में अपलोड कर दिया गया है । संलग्न- एफ0आर0ए0 की छायाप्रति।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
गौचर (चमोली)
24.2.18

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.09 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of New motor road "Langasu-Niwari-Khet-Silangi" in Chamoli district falls within jurisdiction "Langasu, Niwadi, Khet, Silangi, Ulfada & umrakot", in Karanpryag tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.870 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Langasu, Niwadi, Khet, Silangi, Ulfada & umrakot' sub-Division level Committee Karanpryag and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकार

चमोली

ANNEXURE....

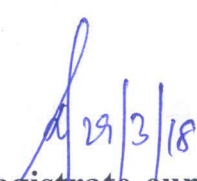
**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Asheesh Joshi, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 29/3/18 at time 11:30 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring **5.680** hect for the construction of motor road "**Langasu-Niwari-Khet-Silangi Motor road**" and forest land **3.09** hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 29.3.2018


**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र-23.2
परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत लंगसू - निवासी - वन-
निर्यात मो० मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~कपूरप्रसाद~~
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~कपूरप्रसाद~~

उपखण्ड ~~कपूरप्रसाद~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत लंगसू - निवासी - वन-
निर्यात मो० मार्ग का निर्माण (1.78 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.21 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.12 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.09 हे० वन भूमि) का
उपखण्ड स्तरीय समिति प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~कपूरप्रसाद~~) की दिनांक 09.02.2010 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री ~~विबेक प्रकाश~~, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~विवेक प्रकाश~~ उप जिलाधिकारी ~~कपूरप्रसाद~~ उप जिला अधिकारी
- 2- श्री ~~अमर कान्त~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~कपूरप्रसाद~~ सदस्य
- 3- श्री ~~मोहन सिंह~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ~~कपूरप्रसाद~~ सदस्य
- 4- श्री ~~मालवी प्रसाद~~ बी०डी०सी० क्षेत्र ~~कपूरप्रसाद~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि राज्य योजना के अन्तर्गत लंगसू - निवासी - वन-निर्यात मो० मार्ग का
नव निर्माण परियोजना हेतु 3.09 हे० वन
भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~मोहन~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008

के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~कृष्णपुरा~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~लंग्रा - बिबाही - देव - सिहरी - मो.मरा~~ परियोजना के निर्माण हेतु हे० वन भूमि ~~३.०२~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ~~कृष्णपुरा~~
जनपद ~~चमोली~~

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ~~चमोली~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ~~कृष्णपुरा~~
जनपद ~~चमोली~~

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

**ग्राम का नाम- लंगासू-निवाडी
तहसील- जिला-चमोली**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल 3.09 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम लंगासू-निवाडी द्वारा दिनांक.....3.02.2016..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि *वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लंगासू-निवाडी के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- ज००एम० न०वाला
ग्राम सचिव ज००एम००वि०अ०


ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक 03.02.16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लगासू निवाडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहन सिंह नेगी	Mohan Singh
2-	भगत सिंह नेगी	Bhagat Singh
3-	नरेन्द्र सिंह खत्री	Narendra Singh
4-	नन्दन सिंह खत्री	Nandani Singh
5-	नरेन्द्र सिंह खत्री	Narendra Singh
6-	नारायण सिंह खत्री	Narayan Singh
7-	भूपेन्द्र सिंह खत्री	Bhupendra Singh
8-	कमल सिंह खत्री	Kamal Singh
9-	लक्ष्मण सिंह नेगी	Laxman Singh
10-	उमराव सिंह नेगी	Umarav Singh
11-	विक्रम सिंह खत्री	Vikram Singh
12-	कमल सिंह खत्री	Kamal Singh
13-	बाहादुर सिंह	Bahadur Singh
14-	बलवीर सिंह नेगी	Balvir Singh
15-	दलवीर सिंह	Dalvir Singh
16-	अनूप सिंह खत्री	Anoop Singh
17-	अश्वान्त सिंह खत्री	Ashwanth Singh
18-	अमित खत्री	Amit Singh
19-	हेमन्त खत्री	Hemant Singh
20-	राजेंद्र सिंह खत्री	Rajendra Singh

ह0/ -
ग्राम प्रधान
लगासू निवाडी

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम- खेत
तहसील- जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल 3.09 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम खेत द्वारा दिनांक 3.02.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खेत के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- ज०एम० जगवाल
ग्राम सचिव ग०प०वि०अ०



प्रपत्र-23.1

दिनांक 22/01/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अमराकोट (बिजौली), मल्ला सेत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	नरेन्द्र प्रसाद रावत	Nee
2-	देवेन्द्र सिंह रावत	देवेन्द्र
3-	आनन्द सिंह रावत	Anand
4-	योगेन्द्र सिंह रावत	योगेन्द्र
5-	कमल सिंह रावत	Kamal
6-	रविन्द्र सिंह रावत	Ravindra
7-	शक्ति सिंह रावत	Shakti
8-	महिपाल सिंह रावत	महिपाल
9-	दिगपाल सिंह रावत	Digpal
10-	प्रेम सिंह रावत	Prem
11-	अनन्तर सिंह रावत	Anantar
12-	सुरेन्द्र सिंह रावत	Surender
13-	गजे सिंह रावत	Gajendra
14-	नरेन्द्र सिंह रावत	Narender

ह0/-

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

दिनांक ३०/१६ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत उमरकोट मैदास (तब्बल खेत)

[illegible]

८०/

ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम- सिलंगी
तहसील- जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल 3.09 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

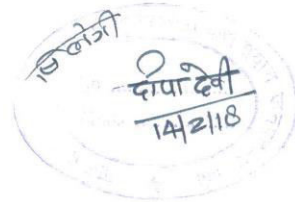
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सिलंगी द्वारा दिनांक 3-02-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिलंगी के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

ग्राम सचिव
ग्राम सचिव
ग्राम सचिव

ह०/-
ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

दिनांक 03/04/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिंहाली चारमुखा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कुन्दन सिंह चौहान	कुन्दन सिंह
2-	आलम सिंह चौहान	आलम
3-	राजीव सिंह चौहान	राजीव सिंह
4-	देव सिंह पुकार	देव सिंह
5-	वीर सिंह पुकार	वीर सिंह
6-	जमवीर सिंह चौहान	जमवीर सिंह
7-	मोहन सिंह पुकार	मोहन सिंह
8-	धर्म सिंह पुकार	धर्म सिंह
9-	दयाल सिंह विक	दयाल सिंह
10-	वीरेंद्र सिंह	वीरेंद्र सिंह
11-	हर्ष सिंह	हर्ष
12-	दरवान सिंह पुकार	दरवान
13-	बलवीर सिंह पुकार	बलवीर
14-	पुकार सिंह	पुकार सिंह
15-		

